भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3211

दिनांक 06 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

.....

राजस्थान में अटल भूजल योजना

3211. श्री हरीश चंद्र मीनाः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार टोंक और सवाई माधोपुर जिलों सहित राजस्थान में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा 'अति-दोहित' या 'गंभीर' घोषित की गई ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार जल सुरक्षा योजनाओं (डब्ल्यूएसपी), जारी धनराशि और निर्मित पुनर्भरण संरचनाओं सहित राजस्थान में अटल भूजल योजना (एबीवाई) की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान में एबीवाई का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो इस संबंध में किए गए/किए जाने के लिए प्रस्तावित सुधारात्मक उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) राजस्थान के अति-दोहित ब्लॉकों में पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए एबीवाई और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीनरेगा) के अभिसरण की स्थिति क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 2022 से देश के सक्रिय भूजल संसाधनों का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जा रहा है। ब्लॉक/मंडल/तालुका/तहसील/जिला (जैसा लागू हो) में किए गए मूल्यांकन में वार्षिक भूजल पुनर्भरण, वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन, वार्षिक भूजल निष्कर्षण और भूजल निष्कर्षण के स्तर का वैज्ञानिक अनुमान लगाया जाता है। मूल्यांकन के आधार पर, मूल्यांकन इकाइयों को 'सुरक्षित', अर्द्ध-गंभीर', गंभीर'और 'अति-दोहित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मूल्यांकन के परिणाम सीजीडब्ल्यूबी के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराए जाते हैं। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ग्राम पंचायतों को अति-दोहित, गंभीर, अर्द्ध-गंभीर' या सुरक्षित घोषित नहीं करता है।

सक्रिय भूजल संसाधन मूल्यांकन, 2025 के अनुसार, राजस्थान में कुल 302 आकलन इकाइयों का मूल्यांकन किया गया है, जिनमें से 36 मूल्यांकन इकाइयों को 'सुरक्षित', 27 को

'अर्ध-गंभीर', 23 को 'गंभीर', 213 को 'अति-दोहित और 3 को 'लवणयुक्त' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

टोंक जिले में, 1 मूल्यांकन इकाई (उनियारा) को 'गंभीर' और 2 मूल्यांकन इकाइयों (मालपुरा और निवाई) को 'अति-दोहित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सवाई माधोपुर जिले में, किसी भी मूल्यांकन इकाई को 'गंभीर' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, जबकि 6 मूल्यांकन इकाइयों (गंगापुर, सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, खंडर, बोनली और बामनवास) को 'अति-दोहित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ख): राजस्थान के 17 जिलों के 38 ब्लॉकों में 1132 ग्राम पंचायतों को अटल भूजल योजना (एबीवाई) के अंतर्गत शामिल किया गया था और इन सभी 1132 ग्राम पंचायतों में जल सुरक्षा योजनाएं तैयार की गई थीं। राजस्थान राज्य में एबीवाई के तहत की गई गतिविधियों/कार्यों का विवरण इस प्रकार है:

राज्य/जिला/ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या	**कुओं की निगरानी**	**मौजूदा जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का मानचित्रण**	**ड्रिप, स्प्रिंकलर, फसल विविधीकरण आदि जैसी कुशल जल-उपयोग प्रथाओं के तहत शामिल क्षेत्र (हेक्टेयर में)**	**चेक डैम, तालाब, रिचार्ज शाफ्ट आदि जैसे आपूर्ति-पक्ष संरचनाओं का निर्माण/नवीकरण।**
17782	17685	19693	89969.88	19126

एबीवाई के तहत राजस्थान राज्य को जारी/सौंपी गई और राजस्थान राज्य द्वारा उपयोग की गई कुल निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

(रूपये करोड़ में)

राज्य	**वितरित निधि**	**उपयोग की गई निधि**
राजस्थान	514.84	513.60

(ग): भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा अटल भूजल योजना का समग्र प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन क्षेत्रों में, विस्तृत फील्ड सर्वेक्षणों और स्थानीय समुदायों के साथ हुए संवाद के आधार पर, इस अध्ययन में योजना द्वारा लाए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों की सार्थकता को स्वीकारा गया है। जैसे क्षमता निर्माण और आईईसी

गतिविधियों के माध्यम से भूजल के मुद्दों पर सामुदायिक जागरूकता में वृद्धि, भूजल प्रबंधन में नेतृत्व और निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी, सामाजिक समावेशिता और समग्र ज्ञान में वृद्धि और भूजल संरक्षण और जल प्रबंधन में भाग लेने के लिए समुदाय की इच्छा। इस रिपोर्ट की एक प्रति जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की वेबसाइट के वेब-लिंक https://www.jalshakti-dowr.gov.in/static/uploads/2026/07/597fd8727a8d10641bd33d7d22ce0459.pdf पर उपलब्ध है:

(घ): राजस्थान के 26 अति-दोहित ब्लॉकों में अटल जल के अंतर्गत 3,309 आपूर्ति पक्ष संरचनाओं के निर्माण/नवीकरण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत 392.92 करोड़ रुपए की राशि का अभिसरण (कन्वर्जेन्स) किया गया था।

*****